मोदी सरकार ने राजस्थान रेलवे के विकास के लिए 9960 करोड़ रु. दिए : मदन राठौड़

'प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 तक राजस्थान में 43918 करोड़ रुपए की लागत से 3409 किलोमीटर लंबाई की 28 रेल परियोजनाओं को किया स्वीकृत'

जयपुर । राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने राजस्थान रेलवे के विकास के लिए 9960 करोड़ रु. दिए है, जो कि यूपीए सरकार से करीब 15 गुणा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 से 14 के दौरान राजस्थान को रेलवे परियोजनाओं के लिए मात्र 682 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का बजट आवंटित हुआ था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान को मिलने वाले रेल बजट में करीबन 15गुणा बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2025-26 में राजस्थान रेल परियोजनाओं के लिए 9,960 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह पीएम मोदी सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की नीति का जीता-

■ **नई रेल लाइनें डलने से जयपुर, अजमेर, उदयपुर व जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और व्यापार के हब बनेंगे : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष**

जागता उदाहरण है। सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को जानकारी दी।

मदन राठौड़ ने बताया कि रेलवे लाइनों के विस्तार में भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2009-14 के दौरान जहां मात्र 798 किमी लाइन का कमीशनिंग हुआ, वहीं 2014-25 की अवधि में यह बढ़कर 3,815 किमी तक पहुंच गया, यानी औसतन कमीशनिंग दर दो गुना से अधिक हुई है। 1 अप्रैल 2025 तक राजस्थान में 28 बड़ी परियोजनाएं (13 नई लाइनें, 5 आमान परिवर्तन, 10 दोहरीकरण) विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी कुल लंबाई 3,409 किमी और कुल लागत 43,918 करोड़ है। इनमें से 1,238 किमी का कार्य पूरा कर लिया गया है और 18,955 करोड़ का निवेश पहले ही हो चुका है।

राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में पूर्ण हुई परियोजनाओं में सूरतपुरा-श्रीगंगानगर, सादलपुर-बीकानेर-रतनगढ़-डेगाना आमान परिवर्तन, जयपुर-रींगस-सीकर-चूरू एवं सीकर-लोहारू समेत अनेक महत्वपूर्ण दोहरीकरण कार्य शामिल हैं। हाल में शुरू हुई परियोजनाओं में पुष्कर-मेडता, तरंगा हिल-आबू रोड, रामगंज मंडी-भोपाल, नीमच-बड़ी सादड़ी, ग्वालियर-श्योपुर कलां (कोटा विस्तार सहित), धौलपुर-सरमथुरा (गंगापुर सिटी विस्तार सहित), मथुरा-झांसी तृतीय लाइन, मावली-देवगढ़ मदारिया गेज परिवर्तन, मारवाड बाई पास लाइन और चूरू-सादुलपुर एवं लूणी-भीलडी दोहरीकरण जैसी मेगा परियोजनाएं शामिल हैं। रेल कनेक्टिविटी को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 55 नई परियोजनाओं के सर्वेक्षण को स्वीकृति दी गई है, जो 5,497 किमी लंबाई तक फैली हैं। इनमें अनूपगढ़-बीकानेर (खाजूवाला शाखा सहित), जैसलमेर-भाभर, खाजूवाला-जैसलमेर और रींगस-लोहारू दोहरीकरण जैसी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। यह सभी परियोजनाएं उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ज़ोन के अंतर्गत संचालित हो रही हैं।

देवस्थान विभाग करेगा धर्मशालाओं का निर्माण

जयपुर । प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए देवस्थान विभाग और अधिक सुविधाओं को विकसित करेगा। इसके लिए विभाग की पूर्व में संचालित धर्मशालाओं व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बना रहा है। इसके तहत पुरानी धर्मशालाओं में सुविधाएं तो विकसित की जाएंगी साथ ही प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अत्याधुनिक नई धर्मशालाओं का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए देवस्थान विभाग अपनी नीति में संशोधन करेगा। इस संबंध में शासन सचिवालय में मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद सहमति हुई। बैठक में पूर्व संचालित धर्मशालाओं के किराए में बढोतरी करने व बीओटी (बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर) के तहत नई धर्मशालाओं के निर्माण के लिए नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा की क्रियान्विति को लेकर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

सार-समाचार

एड्स के प्रति जागरूकता सेमीनार

जयपुर । अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ओटीएस स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित रेड रिबन क्लब के सदस्यों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इंटेंसिफाइड आईईसी कैम्पेन का शुभारंभ किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक एवं अन्य रोचक प्रस्तुतियों के द्वारा एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता का संदेश युवाओं को दिया गया। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के परियोजना निदेशक शाहीन अली खान ने कहा कि देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले, इसी उद्देश्य से प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इंटेंसिफाइड आईईसी कैम्पेन का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विशेषकर युवाओं तक एचआईवी/एड्स की जानकारी पहुंचाने के लिए जांच व परामर्श की सुविधा एवं कैंप का आयोजन, फ्लेश मॉब, रैली, डोर-टू-डोर कैम्पेन, सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालयों में एचआईवी/एड्स पर जागरूकता सत्रों का आयोजन, ग्राम स्तर पर मीटिंग के साथ कला जत्था गतिविधियां, सोशल मीडिया पर जागरूकता संदेश के साथ ही साथ राजकीय अस्पतालों में विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान 2 माह तक चलेगा। संयुक्त निदेशक, आईईसी डॉ. प्रदीप चौधरी ने कहा कि युवाओं को एचआईवी एवं यौन व प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी हेतु राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लबों की स्थापना कर समग्र शिक्षा के लिए उनका क्षमतावर्धन किया है। आज 755 रेड रिबन क्लबों के माध्यम से महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एचआईवी की जानकारी से लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम से मुलाकात

जयपुर । अखिल राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (ए.आर.यू.टी.ए.) के अध्यक्ष प्रो. बी.डी. रावत ने बताया कि वरिष्ठ शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला और उन्हें इस विषय में अवगत कराया कि कैरियर उन्नयन योजना (सी.ए.एस.) के अंतर्गत प्रोफेसर पद का लाभ उन शिक्षकों को अब तक नहीं दिया गया है, जिन्हें चयन समिति द्वारा विधिवत चयनित किया गया था तथा जिनका चयन 25 सितम्बर 2021 को सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन शिक्षकों को वेतन निर्धारण (फिक्सेशन) का लाभ और सेवा की गणना नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से करने का लाभ भी सुप्रीम कोर्ट के 29 नवम्बर 2018 के आदेश के अनुसार नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित प्रभारी अधिकारी को उच्च शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मंगाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि वरिष्ठ शिक्षकों का यह लंबित मुद्दा शीघ्र ही सुलझाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने उनके आवास पर जाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से भेंट की और उन्हें भी इस लंबित मुद्दे की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के 29/11/2018 के निर्णय के आलोक में, यूजीसी के प्रावधानानुसार विधिवत चयन समिति प्रक्रिया से चयनित तथा सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ शिक्षकों को सी.ए.एस. प्रोफेसर पद का लाभ देने और वेतन निर्धारण (फिक्सेशन) सहित अन्य लाभ शीघ्र देने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल में प्रो. एम.एस. शर्मा, प्रो. बी.एल. गुप्ता, प्रो. आर.के. अग्रवाल, प्रो. मधु भट्ट तैलंग एवं प्रो. दलवीर सिंह शामिल थे।

बाबू अंसारी बने प्रदेश महासचिव

जयपुर । राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नसीम अंसारी ने बाबू अंसारी को प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत किया। बाबू अंसारी की सक्रियता, सामाजिक जुड़ाव और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन देश के 22 राज्यों में समाज के उत्थान, शिक्षा, युवाओं को जागरूक करने और एकता को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। वहीं बाबू अंसारी ने प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नसीम अंसारी का आभार जताते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करेंगे। उनका लक्ष्य संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, समाज के लोगों की आवाज को मजबूत मंच पर उठाना और युवाओं को जोड़ना होगा।

मोजम्बिक में 1230 विकलांगों का पुर्नवास

जयपुर । अफ्रीकी देश मोजम्बिक की राजधानी मापूतो में भारत सरकार और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशेष शिविर में कुल 1230 विकलांगों का पुर्नवास किया गया । उल्लेखनीय है कि मोजम्बिक की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने इस पुर्नवास शिविर का आयोजन किया था । विष्णुकांत शर्मा के नेतृत्व में बी.एम.वी.एस.एस. के 13 सदस्यीय दल ने मोजम्बिक के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से मापूतो के सेन्ट्रल अस्पताल में इस निःशुल्क शिविर का आयोजन किया था । शिविर के समापन समारोह में मोजम्बिक के स्वास्थ्य मंत्री उसैन इस्से ने भारत सरकार को इस शिविर के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस शिविर के आयोजन से ऐसे विकलांगों को चलने-फिरने का सुखद अनुभव हुआ जो विकलांगता के कारण असमर्थ थे । समारोह में भारत के राजपूत राबर्ट शेटकिंग टॉग ने कहा कि भारत-मोजम्बिक की मैत्री पुरानी हैं और भारत सरकार ने मोजम्बिक की आजादी की स्वर्णजयन्ती के अवसर पर इस शिविर का आयोजन "इण्डिया फॉर ह्यूमैनिटीज" कार्यक्रम के अन्तर्गत कर सौहार्द का परिचय दिया हैं । बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने कहा कि बी.एम.वी.एस.एस. ने 41 देशों में 114 अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन कर 40 हजार विकलांगों को लाभ दिया हैं । डी.आर. मेहता ने कहा कि मोजम्बिक में अभी भी बड़ी संख्या में विकलांग हैं जिनके पुर्नवास के लिए निजी संस्थाओं के सहयोग से एक और शिविर उत्तरी मोजम्बिक के नाम्पूला में प्रस्तावित हैं जिसकी तैयारियां चल रही हैं ।

75 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवगण को निर्देश दिए है कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र में विधायकगण द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों के जवाब राजस्थान विधान सभा को आगामी सत्र के आरम्भ होने से पहले 27 अगस्त तक आवश्यक रूप से भेज दिए जाएं। देवनानी ने बताया कि सोलहवीं विधानसभा के तृतीय सत्र में विधायकगण द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से लगभग 75 प्रतिशत के जवाब राज्य सरकार से विधानसभा को प्राप्त हो गए है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधान सभा को लगभग 9700 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से 7300 प्रश्नों के जवाब मिल गए है। लम्बित 2400 प्रश्नों के जवाब विभिन्न विभागों से आना शेष है। उन्होंने बताया कि तृतीय सत्र के बकाया प्रश्नों के जवाब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आगामी सत्र से पहले 27 अगस्त तक प्राप्त हो जाएंगे। देवनानी ने कहा कि सोलहवीं विधानसभा का चतुर्थ अधिवेशन, जो 1 सितंबर से प्रारंभ होगा, इससे पहले सभी लंबित प्रश्नों के उत्तर विधान सभा को भेजे जाने के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए विधान सभा द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब आना आवश्यक है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की प्रदेश की आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत पर चर्चा

जयपुर (कासं)। उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई जिसमें महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त समग्र शिक्षा अनुपमा जोरवाल, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारी उपस्थिति हुए। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जून माह के सर्वे अनुसार 6012 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करवाये जावे। प्रथम चरण में 50 करोड़ की लागत से 3033 केंद्रों की मरम्मत की वित्तीय स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा 2365 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के भी निर्देश दिए गए है। उन्होंने अगले 4 महीनों में आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के कार्य को निष्पादित करने के निर्देश दिए। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग समसा में जेईएन/एईएन की प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त चार्ज दें।

25 लाख की छात्रवृत्ति और 8 स्कॉलर्स अवार्ड

जयपुर । रूमा देवी फाउंडेशन और गढ़वाल फैमिली फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को कांस्टीट्यूशन क्लब, जयपुर में "रूमा देवी सुगनी देवी अक्षरा छात्रवृत्ति 2025" के कार्यक्रम के द्वितीय चरण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुई। इस अवसर पर कुल 25 लाख रुपये की छात्रवृत्ति जरूरतमंद और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रदान की गई। साथ ही, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाली ग्रामीण पृष्ठभूमि की 8 बेटियों को 1-1 लाख रुपये के स्कॉलर्स अवार्ड देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि कार्यक्रम की पहलकर्ता डॉ. रूमा देवी, जिन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी, आज ग्रामीण भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्तंभ हैं।

बिना परमिट और टैक्स चोरी में 39 वाहन ज़ब्त

जयपुर । राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की सचिव एवं आयुक्त सुची त्यागी के सख्त निर्देशों के तहत आरटीओ जयपुर द्वितीय ने मंगलवार को एक और विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। यह कार्रवाई अचानक और योजनाबद्ध तरीके से की गई। जिसका उद्देश्य था- बिना परमिट, टैक्स चोरी, रोडवर्दीनेस उल्लंघन और अवैध यात्री ढुलाई में संलग्न वाहनों पर शिकंजा कसना।

राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की सचिव एवं आयुक्त सुची त्यागी के अनुसार यह अभियान तीन चरणों में चलाया गया।

जयपुर-चोमू मार्ग पर निजी नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों द्वारा अवैध यात्री ढुलाई की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 18 वाहन जब्त किए गए।

चौमूं कालाडेरा मार्ग पर अवैध यात्री ढुलाई और टैक्स चोरी में लिप्त 11 वाहन पकड़े गए, जिनमें से 6 वहीं सुपुर्द किए गए। प्रतापगढ़ अलवर क्षेत्र में भी अचानक दबिश देकर बिना परमिट व टैक्स चोरी में शामिल 10 वाहन जब्त किए गए। इस संयुक्त अभियान में चंदवाजी, चोमू, कालाडेरा और प्रतापगढ़ थानों के थानाधिकारियों और पुलिस बल ने तत्काल सहयोग करते हुए मौके पर ही वाहनों की ज़ब्ती सुनिश्चित की।

जिला परिवहन अधिकारी यशपाल यादव (शाहपुरा), अतुल कुमार शर्मा (जयपुर द्वितीय), अनूप सहारिया (चोमू) सहित मोटर यान निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की विशेष टीम ने भाग लिया। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66, 192, 39, 192 और 207 के तहत की गई, जिनमें बिना परमिट, टैक्स चोरी, बिना पंजीकरण और वाहन ज़ब्ती के प्रावधान शामिल हैं।

परिसीमन सहित अन्य मुद्दों की 434 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के विभिन्न मुद्दों से जुडी करीब 434 याचिकाओं पर लगातार चार दिन तक सुनवाई कर मंगल वार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने जोधपुर व जयपुर पीठ में दायर करीब 434 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इन याचिकाओं में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव टालकर प्रशासक लगाने, परिसीमन में गाइडलाइन की अवहेलना व वार्ड खत्म होने के कारण आधार पर प्रधान हटाने को चुनौती दी गई। प्रशासक लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा कि संविधान में पांच साल के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त कर चुनाव दिए। परिसीमन के मामलों में राज्य सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना की जा रही है। कुछ याचिकाएं ऐसी भी हैं, जिनमें वार्ड समाप्त होने के आधार पर प्रधान हटाने को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं का महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन से संबंधित मामलों में कोर्ट दखल नहीं कर सकता और परिपत्र या गाइडलाइन से किसी का हक सृजित नहीं हो जाता। इसके अलावा गाइडलाइन में शिथिलता भी दी जा सकती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सभी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

देशभक्ति के रंग में रंगा झोटवाड़ा

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत वार्ड नं. 43 समेत पूरे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उत्साह और देशभक्ति देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में झोटवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रति गर्व की भावना को सशक्त कर रहा है। झोटवाड़ा में यह पहल हर घर तिरंगा अभियान को और मजबूती प्रदान कर रही है। कर्नल राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर हर घर तिरंगा अभियान देशभर में जन-जन का अभियान बन चुका है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस अभियान में सहभागी होकर अपने-अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराएँ।

किसान महापंचायत ने केन्द्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा

जयपुर । किसान महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसान महापंचायत ने ज्ञापन दिया। जिसमें प्रकट किया कि "2014 से लेकर 2025 तक की अवधि में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय समझौते के संबंध में अमेरिकी दबाव के बावजूद किसानों के साथ खड़े दिखाई दिए। जैसे पोकरण परमाणु विस्फोट 1998 के समय अमेरिका की धमकियों के सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई झुके नहीं वरन अमेरिका द्वारा घोषित प्रतिबंधों को भारत के आग्रह के बिना स्वत: ही वापस लेने को विवश होना पड़ा था। किसान यह आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री इसी तरह अमेरिका के समक्ष अडिग रहकर भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करते रहेंगे! किसान यह भी आग्रह करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी क़ानून पारित कर विभिन्न फ़सलों के सरकार द्वारा घोषित एमएसपी किसानों को मिलना सुनिश्चित कर देश को समृद्धशाली बनाने की दिशा में सार्थक पहल करें।" आज के कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि कृषि मंत्री ने मंच से अपने सम्बोधन में केवल किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का ही नाम लिया। इसके अतरिक्त किसान महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कृषि मंत्री को 6 अक्टूबर की "अन्नदाता हुंकार रैली" जयपुर का पम्पलेट निमंत्रण दिया।

पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई

जयपुर । जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने मंगलवार को सांगानेर सदर थाने पर जनसुनवाई कर मौके पर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत रिस्पॉन्स देने और निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (प्रथम) मनीष अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज, पुलिस उपायुक्त पूर्व संजीव नैन, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दक्षिण ललित किशोर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व आशाराम चौधरी, सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर,मानसरोवर एवं चाकसू एवं संबंधित थानाधिकारी और थाने के अधिकारी उपस्थित रहें।

इस दौरान पुलिस थाना सांगानेर, प्रताप नगर, रामनगरिया, मालपुरा गेट, चाकसू, शिवदासपुरा, सांगानेर सदर, कोटखावदा, मानसरोवर, शिप्रापथ एवं मुहाना क्षेत्र के परिवादियों की जनसुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है। जनसुनवाई के दौरान जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान परिवादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस सकारात्मक पहल से आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर बढ़ रहा है। आमजन को राहत देने के लिए सभी थानों में भी प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है।

चोर गिरफ्तार

जयपुर । खोह नागोरियान थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चुराने वाले दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से पुलिस ने पांच चोरी के दुपहिया वाहन जब्त किए है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार वाहन चोरो के खिलाफ पूर्व मे चरणों वाहन चोरी के मामले दर्ज है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन ने बताया कि खोह नागोरियान थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चुराने वाले वाहन चोर नमोनारायण मीना उर्फ लाला और अंकित मीना को गिरफ्तार किया।

वैशाली नगर पुलिस ने चेन स्नैचर गैंग पकड़ी

जयपुर । वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेन तोड़ने वाली एक शातिर गैंग को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में पांच महिला समेत दो पुरुष शामिल है। जिनके पास से पुलिस ने आठ सोने की चेन बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने इस गैंग के पास से दो कार भी जब्त की है । जिन्हें यह गैंग चैन लूटने के लिए इस्तेमाल करते थे।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेन तोड़ने वाली एक शातिर गैंग के शातिर आरोपित विमलेश कुमारी (42) निवासी कोतवाली जिला भरतपुर, पुजा (25) कुमार निवासी बानसुर जिला अलवर, मधु (21) निवासी बानसुर जिला अलवर, गुड्डी (50) निवासी कोतवाली जिला भरतपुर, अंजु (25) निवासी कोतवाली जिला भरतपुर, सुरेन्द्र सिंह बावरीया (47) निवासी कोतवाली जिला भरतपुर और रिषि कुमार बावरीया (33) निवासी बानसुर जिला अलवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि यह गैंग मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजन, कलश यात्रा के दौरान अलग-अलग राज्यों में जाकर वारदात को अंजाम दिया करते थे। जयपुर में सवान माह में इस गैंग ने वैशाली नगर थाना इलाके में आने वाले झारखंड महादेव मंदिर में महिलाओं की चेन तोडी थी। झारखंड मंदिरमें चेन लूट की वारदात की जानकारी सामने आने पर इस पर डीएसटी और थाना पुलिस को एक्टिव होकर पर नजर रखने के लिए कहा गया। मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज में कुछ महिलाएं देखी गई। इनके बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस टीम को इन बदमाशों की लीड मिली। इस दौरान यह गैंग दिल्ली निकल गई। एक टीम ने दिल्ली तक पीछा किया।इसके बाद पता चला कि ये लोग ग्वालियर में एक शिव मंदिर में चले गए हैं। पुलिस टीम निरंतर इनके पीछे रही।

13 से 15 अगस्त तक प्रभारी अधिकारी रहेंगे जिलों के दौरे पर

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह के निर्देश पर यह दल मौसमी बीमारियों सहित स्वास्थ्य सेवाओं की करेंगे गहन समीक्षा

जयपुर । मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव गतिविधियों सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के सघन निरीक्षण के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारियों की टीमें सभी जिलों में जाएंगी। ये टीमें जिलों में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जिसके आधार पर राज्य स्तर से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम के आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभारी अधिकारी संबंधित जिलों में जाकर मौसमी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लें। वे हर जिले में दवाओं और मानव संसाधन की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता, चिकित्सा संस्थानों के भवनों की स्थिति, साफ-सफाई सहित अन्य पैरामीटर्स पर गहन जांच करें। साथ ही, रोगियों एवं उनके परिजनों से भी फीडबैक प्राप्त करें, ताकि वस्तु स्थिति के अनुसार एक्शन लिया जा सके।

जहां केस ज्यादा, वहां करें विशेष फोकस

खींवसर ने कहा कि यद्यिप मौसमी बीमारियों के केस फिलहाल अधिक नहीं हैं, लेकिन जहां भी अपेक्षाकृत केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां बचाव व रोकथाम गतिविधियों पर विशेष फोकस करें। उन्होंने वीसी के माध्यम से जुडे सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों व संबंधित जिला अधिकारियों से गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बारिश का दौर धीमा होने के बाद अब मच्छरों की रोकथाम के लिए फोगिंग, एंटीलार्वल, घर-घर सर्वे सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ाएं।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से चिकित्सा विभाग के सभी कार्मिकों की 31 अगस्त, 2025 तक जिओ मैपिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही, अधिकारी यह बताएं कि कौनसे ट्रोमा सेंटर एवं एफआरयू मानव संसाधन की कमी के कारण क्रियाशील नहीं हैं तथा किस चिकित्सा संस्थान में बैड एवं अन्य मापदण्डों के अनुरूप स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। उन्होंने सीएचओ के रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह सभी जानकारी शीघ्र राज हैल्थ पोर्टल पर अपडेट करें।

खींवसर ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में अब तक करीब 24 हजार पदों पर भर्ती की जा चुकी है तथा लगभग 26 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों में स्टाफ की समुचित उपलब्धता हो। एक पद पर दो व्यक्ति अगर कहीं हों तो तत्काल प्रभाव से एपीओ किया जाए। पिछडे इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर भवनों की स्थिति जांचें। अगर कोई भवन जर्जर हालत में है तो उसे तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जर्जर घोषित करवाएं। साथ ही, जहां भी मरम्मत की आवश्यकता है तुरंत प्रभाव से मरम्मत करवाएं। इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड ने शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों की समक्षा की। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत सीएचओ के कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कार्मिकों के ठहराव पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह भी ध्यान दें कि स्वास्थ्य केन्द्रों से रोगियों का अनावश्यक रैफरल न हो। उन्होंने गांव-ढाणियों में झोलाछाप चिकित्सकों को हटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निःशुल्क दवा व जांच योजना के तहत सभी दवा व जांच सेवाओं की उपलब्धता रखें। मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी से लेकर स्कूलों में बच्चों में विकासात्मक देरी संबंधी 4 प्रमुख विकृतियों की गुणवत्तापूर्ण स्क्रीनिंग के साथ सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आरबीएसके के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में माइक्रोप्लानिंग, लक्ष्य निर्धारण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने आरबीएसके में संचालित सभी मोबाइल हैल्थ टीमों की गाडियों पर अगले 15 दिन में जीपीएस एक्टिव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिलेवरी प्वॉइंट्स पर न्यूबोर्न स्क्रीनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समिति में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करें।